किसानों को राहत

5093. **श्री बंश नारायण सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उर्वरकों का मूल्य तथा सिंचाई के लिये पानी की दरें बढ़ रही हैं और अनाज का भाव लगातार गिर रहा है, क्या किसानों को राहत देने के लिये कोई कार्यवाही करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). यद्यपि खाद्यान्नों के मौजूदा मूल्य 1967 के मुकाबले में कुछ कम हैं, तथापि 1965 और 1966 की तुलना में सामान्यतया ऊंचे चले आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त, उपलब्धि मूल्यों पर, जिससे प्रोत्साहन दिया जाता है, खाद्यान्न मंडियों को सहायता दी जा रही है। इसके अलावा कृषि आदानों के बढ़े हुए मूल्यों की, सामान्यतया क्षति पूर्ति नई तकनीकों को अपनाने के परिणाम-स्वरूप काफी अधिक उत्पादन प्राप्त करके हो जाती है। सरकार की नीति यह है कि जहां अनिवार्य कृषि आदानों के मूल्यों को ध्यान में रखें वहां यह भी सुनिश्चित करें कि कृषक लोग ऋण और आदानों की तत्काल उपलब्धि के रूप में बढ़ी हुई सुविधाओं को प्राप्त करें, ताकि अधिक रुपया लगाना हतोत्साहित करने वाला न बन सके।

मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश) में लघु सिंचाई की सुविधायें

5094. **श्री बंश नारायण सिंह** : क्या **खाद्य तथा कृषि** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मिर्जापुर जिले के दक्षिण भाग में सिंचाई के साधन जुटाने का विचार है, जहां इस समय न तो नलकूप हैं और न कोई नहर ही ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ख). राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और मिलते ही सभा पटल पर रख दी जायेगी।

ACQUISITION OF LAND FOR REFUGEES IN ASSAM

5095. SHRIMATI JYOTSNA CHANDA: Will the Minister of LABOUR AND REHABILITATION be pleased to state:

(a) the number of refugee colonies established in Assam since the year 1950 in each district;

(b) the amount advanced to the District authorities as acquisition cost of land for the refugee colonies;

(c) whether it is a fact that land requisitioned in Nowgong District is now declared to be khas lands; and

(d) whether it is also a fact that eviction notices have been issued against the refugees settled under Government auspices after requisition of grant lands of Shalna and Sarisbari Tea Estates and also to several other refugees settled in such Government colonies?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF LABOUR, EMPLOYMENT AND REHABILITATION (SHRI D. R. CHAVAN): (a) A statement is laid on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT—1835/68].

(b) to (d): The information is being collected from the Government of Assam and will be laid on the Table of the Sabha.